स्वरोजगार के इच्छुक नए उद्यमियों पर मेहरबान होगी योगी सरकार

राजीव दीक्षित • लखनऊ

- दो लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए खोलेगी खजाना
- होनहार छात्रों के लिए शुरू होगी चैंपियन योजना, राज्यस्तरीय प्रतिभा खोज भी

बजट 2024-25

योगी सरकार विधानमंडल में पांच फरवरी को पेश किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के जरिये उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखकर स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी। ऐसे नए उद्यमियों को दो लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार बजट में 1000 करोड़ रुपये की बड़ी रकम आवंटित कर सकती है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती 24 जनवरी को यूपी दिवस पर राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।

योगी सरकार कक्षा एक से तीन तक तक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निपुण भारत के अंतर्गत चैंपियन पुरस्कार योजना शुरू करेगी। बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। वहीं पहली से आठवीं कक्षा तक के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सभी जिलों में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने का नया एलान भी बजट में हो सकता है। टाटा टेक्नोलाजीस के सहयोग से प्रदेश में 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का तकनीकी उन्नयन किया जा रहा है। सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश के 69 और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन के लिए बजट में लगभग 800 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर सकती है। प्रदेश में दो मेगा राजकीय आइटीआइ की स्थापना किए जाने की घोषणा भी की जा सकती है। सरकार ने पिछले बजट में गोंडा, मीरजापुर और मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 50-50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की थी। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में भी तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 50-50 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा सकती है।

बुनियादी ढांचे के विकास को भी बजट में अहमियत मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए भी बजट आवंटन की प्रबल संभावना है। शहरों में 10 से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए लागू की गई सीएम ग्रिड्स योजना तथा अमृत 2.0 व स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए भी सरकार बजट में बड़ी रकम का इंतजाम करेगी।

बीते दिनों लागू की गईं सेमीकंडक्टर नीति और फार्च्यून 500 कंपनियों को खासतौर पर आकर्षित करने के लिए लाई गई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भी बजट में भरपूर राशि की व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी सरकार धनराशि देगी।

अयोध्या पर होगी धनवर्षा

बजट के माध्यम से सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लौ को और प्रदीप्त करेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार खजाना खोलेगी। रामनगरी में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन पर खास फोकस होगा। अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा को भी बजट में महत्व मिलने की पूरी संभावना है। नैमिषारण्य, शुक्र तीर्थ और देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद के लिए भी बजट में संसाधनों की व्यवस्था होगी।